

Regarding Hydro Power Project

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : माननीय चेयरपर्सन मैडम, मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ।

वर्ष 2007 में, अरुणाचल प्रदेश की सरकार और पावर मिनिस्ट्री के बीच में 2,880 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एक एमओयू हुआ था। अभी उस प्रोजेक्ट का काम काफी हद तक आगे बढ़ा है। उस एमओयू में प्रावधान किया गया था कि रिक्रूटमेंट में ग्रुप सी और ग्रुप डी स्टाप्स में 100 परसेंट लोकल लोग होंगे और 20 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियर ऑफिशियल्स डेपुटेशन पर होंगे। People through the local contractors other than the major construction works, and local producers and manufacturers के लिए उस एमओयू में साइन हुआ है।

ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर यहां हैं।

मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस इलाके की लोकल कम्युनिटी को आथोराइज़ होने से पहले इस एमओयू के आधार पर, वहां के लोकल्स को बेनिफिट देना चाहिए, यह मैं मांग करता हूँ।